SHRI ARIF MOHD. KHAN: I am sure that the hon. Member will appreciate that it is not a question of sharing information just for the sake of sharing information. It is a question of sharing information for safety purposes. With whom has this information been shared? This information has been shared with the persons who are flying the aircraft. *(Interruy_ tions)* Now my problem is that I have shared this information with the specific purpose of ensuring the safety of the travelling public, those who are flying by this aircraft, not necessarily in India but even outside India also. Officially it is known that they have access to this information. Now if somebody, after having gained access to this information tries to plant wrong information in the newspapers, I have no check on that. I

. आपने

कम्प्यूटर के बारे में पूछा है। यह बहुत टेक्निकल

computers will operate up to 51 degree centigrade.

cannot do anything about it

computers will operate up to 51 degree centigrade

लेकिन आप जितना डिटेल .

SHRI SURESH KALMADI: Madam. they are not going to fly without the Court of Inquiry report coming out. The people have a right to know what had gone wrong. *(Interruptions)*

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam, I would like to state with all the force at my command that no compromise will be made and no chances will be taken as far as the safety of the travelling public is concerned. No risk will be taken, no chance will be taken and no compromise will he made. We are fully alive and we will ensure that the safety standards are fully enforced. There is no question of taking any chance, any risk or making any compromise as far as the safety requirements are concerned. Thank you, very much.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, much has been written in the news, papers and much has been reported and questions are being raised. Before the A-320 aircraft is reintroduced, I think a sort of confidence needs to be developed among the passengers or among the masses who travel by air. I agree with the hon. Minister that the Pilots who will be piloting those aircraft must be assured of the safety aspect of that aircraft. Similarly, the passengers need to be assured. But already due to may be disinformation or various other reasons, a sort of disinformation is percolating down. Therefore, before A-320 aircraft is reintroduced, I would expect the Minister of Civil Aviation to take steps so that a sense of confidence is created among the masses who travel by air.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I totally agree. It will not merely be an exercise. It will be a genuine confidence-building exercise. As I have said earlier, we have already given instructions. Very intensive checks are being carried out by the teams which have been constituted by the Director-General of Civil Aviation in Delhi, Hyderabad and in Bombay. I would like to further assure the hon. Members of this House that on the question of enforcement of safety standards we will not make any compromise, we will not take any chance and we will not risk the human lives. We have also given instructions to the D.G.C.A. to ensure that this minimum snag list to which I have referred earlier in my Statement must be revised and the aircraft must not be allowed to fly with the snags.

**MOTION OP THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—contd.**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा) : मैडम डिप्टीचेयरमन, जो प्रेजीडेंट के अभिभाषण के ऊपर सदन के अंदर बहस चल रही है और जिसका प्रस्ताव माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने हाउस के सामने पेश

किया, उन्होंने गवर्नमेंट की जो एचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र करते-करते कुछ इलेक्शन के बारे में भी कहा । जो अभी स्टेट्स असेम्बली के इलेक्शन हुए उनसे पहले लोक सभा के इलेक्शन हुए थे । इलेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने अमेठी का जिक्र किया । उनसे कहना चाहता हूं कि लोक सभा के इलेक्शन के जिक्र के साथ थोड़ा सा रिजल्टली असेम्बली के जो इलेक्शन हुए उनके बारे में भी जिक्र कर देते तो अच्छा होता । मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वीरेन्द्र वर्मा जी जैसे शरीफ़ आदमी हाउस के अंदर है, जहां तक मेरा उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन जैसे शरीफ़ आदमी हाउस के अंदर खड़े होकर यह कहें कि वहां महम के अंदर 8 ही मरे हैं इससे ज्यादा अफ़सोसनाक बात और क्या हो सकती है । आप सब जानते हैं कि महम के अंदर क्या-क्या हुआ । वीरेन्द्र वर्मा जी अगर उसको दबाना चाहें तो क्या कहा जा सकता है । क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए इलेक्शन के बारे में जिक्र किया था इसलिए इस पर कंट्रैस्ट करना चाहता हूं अपने आपको । महम के अंदर जिस तरह से खून-खराबा हुआ, जिस तरह से डेमोक्रेसी का खून हुआ है उन वाकयात को देखते हुए मैं समझता हूं जो आदमी वहां जाने वाले थे, अखबार वाले थे, फ़ोरेन प्रेस वाले थे या इंडियन प्रेस वाले थे उन्होंने जो कुछ कहा वह बयान से बाहर है । यह पालिटिशनस की आदत हो गयी है कि प्रेस कुछ भी लिखे, या जो वहां हकीकत है उसको पब्लिक के सामने रखे, उसको मानने के बजाय प्रेस वालों को गालियां देने लग जाते हैं । हिन्दुस्तान की प्रेस ने ही नहीं बल्कि फ़ोरेन प्रेस, बी० बी० सी० ने भी महम के इलेक्शन पर काफ़ी कुछ कहा है । मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का बिहेवियर महम के बारे में था । That has been reduced to a farce. सारी प्रेस ने बार-बार बीस दिन तक लिखा, लोगों की आवाज आती रही, वहां पर इलेक्शन लड़ने वाले कंडीडेट्स भी यह कहते रहे कि वहां पर खून-खराबा किया जायेगा क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर यह तय किये हुए थे कि हारी हुई लड़ाई को किसी भी कास्ट पर जीतना है । मैडम, श्री वीरेन्द्र वर्मा अभी यहां पर नहीं हैं, कुछ दोस्त वहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह मामूली बात है कि महम के सारे हालात को देखते हुए आपकी पार्टी को यह डिसीजन लेना पड़ा कि महम के अन्दर दुबारा इलेक्शन करवाये जायें, रिइलेक्शन करवाया जाये । यह कोई छोटी बात नहीं है । चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने सारे हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, इंडिक्ट किया है, बुरे लफ्जों में इंडिक्ट किया है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल किया गया है । इसको आप जाने दीजिये । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी में शर्म हो तो वह शर्म करे । सर्वजातीय, सर्वखाप पंचायत ने महम के अन्दर कोई 25-30 हजार आदमी इकट्ठा किए । डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनको आप ताऊ कहते हैं, चौधरी देवीलाल, उनकी परफ़ारमेन्स आपने हाउस में देख ली है, उनका कैलिबर देख लिया है, उनको बिरादरी से खारिज कर दिया गया, उनका हुक्का पानी बन्द कर दिया गया । अब उनकी कोई इज्जत नहीं है । यानी पानी में डूबते हुए तो आपने लोगों को देखा होगा, लेकिन कल्लर में कोई डूबता नहीं देखा होगा । डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनका लड़का जो हरियाणा में चीफ़ मिनिस्टर है, वे कल्लर में डूब सकते हैं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : यह कल्लर क्या होता है ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : बगैर पानी की जगह को कल्लर कहते हैं । पानी में तो सब डूब सकते हैं, लेकिन इसमें डूबते हुए आपने कोई नहीं देखा होगा । लेकिन ये डूब सकते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि ये लोग हुकूमत किस की चला रहे हैं ? क्या इनकी हुकूमत चल रही है ? इनकी हुकूमत चल रही है बी.जे.पी. और लेफ्ट पार्टीज के बलबूते पर । ये इनके एलाइंज हैं । दोनों सी.पी.आई. और सी.पी.एम. तथा बी.जे.पी. ने इनके चीफ़ मिनिस्टर से इस्तीफ़े की मांग की है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी

[श्री मुख्तियार सिंह नलिक]

जो बी.जे.पी. के इस हाउस में लीडर हैं और श्री आडवानी जो लोक सभा में लीडर हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सबने इनको पहले अपनी सपोर्ट दी, लेकिन सी.पी.आई. और सी.पी.एम. ने भी अपनी सपोर्ट विदड्रा कर ली है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यहां पर हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि हम हुकूमत चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो मैं देवीलाल से बड़ा हूं, लेकिन पिछले 35 साल से पोलिटिक्स में उनके साथ रहा हू और उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वे हमेशा डिस्ट्रक्टिव पालिसी के ऊपर चलते हैं। वे अपनी किसी बात पर टिकते नहीं हैं। व तो भस्मासुर हैं। वाणासुर राक्षस का नाम आपने सुना होगा। भस्मासुर अपनी आग में खुद जल जाता है। श्री देवीलाल भी खुद ही जल जाएगा। जनता दल वालों, अगर बचना चाहते हो, बी० जे० पी० वालों और सी०पी०आई० वालों, बचना चाहते हो तो तुम्हारे सिर के ऊपर जो यह उल्लू बैठा है, एक छोटी कोतरी भी होती है जो उल्लू जैसी ही होती है, वह किसी के सिर पर बैठ जाय तो बड़ा बद्शकुन माना जाता है। वह किसी दरख्त पर बैठ जाये तो वह जल जाता है। तुम्हारे सिर के ऊपर यह उल्लू बैठा हुआ है, यह तुम्हें लेकर डूबेगा। जिस्म के अन्दर फ़ोड़े-फ़ुंसी हो जायं तो खुजली करके दर्द को दूर किया जा सकता है। लेकिन शरीर के अन्दर कोढ़ हो जाय, या पीप पड़ जाय तो उसका इलाज फ़कत मौत ही है। पीप और कोढ़ी का इलाज ही यही है।

तो मैं यह समझता हूं कि जनता दल की हुकूमत, वर्मा जी कह रहे थे कि पांच साल तक चलेगी। जिस वक्त व बोल रहे थे मैं उस वक्त बताना चाहता था, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं पर मैंने हालात ऐसी नहीं देखी जिससे यह सही हो। मेरा तजुर्बा है 1977 में मैं वर्मा जी की जगह बैठा हुआ था और वर्मा जी मेरी जगह बठ हुए थे। मैंने कहा जब उन्होंने तुर्कमान गेट का जिक्र किया कि आप कहां थे, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई तुर्कमान गेट के ऊपर। लेकिन खैर मैं जेल में था 18 महीने इमरजैंसी के अंदर और वहां से बाहर आने के बाद मैंने जनता पार्टी की हुकूमत देखी। वर्मा जी कहने लगे कि परिणाम देखने के लिये पांच साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं उस वक्त उनसे कहना चाहता था, कि मैं ज्योतिषी तो नहीं लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने तो ढ़ाई साल निकाल लिये थे 1977 में, लेकिन यह जनता दल पांच महीने भी नहीं निकाल सकता है। अगले दिन भी नहीं बल्कि उसी दिन शाम को ऐसा धमाका मारा चौधरी देवीलाल ने, आजकल हरियाणा के अंदर उनको धृतराष्ट्र कहते हैं क्योंकि रोजाना हर एक इतवार को लोग महाभारत देखते हैं, उसके अंदर धृतराष्ट्र आंखें बन्द किये हुए बैठा है। उसका लड़का किसी की बेइज्जती करे कोई परवाह नहीं। वहां पर न भीष्म पितामह हैं, न द्रोणाचार्य हैं, न कृपाचार्य हैं। धृतराष्ट्र आंखें बन्द किये हुए हैं और लड़के ने जो कुछ कर दिया वह सब ठीक है। देवीलाल तो आंखें बन्द किये हुए हैं लेकिन आप लोगों ने क्यों आंखें बन्द कर लीं? यह आपके चलने का ढ़ंग है। ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है। हरियाणा से चौटाला को क्यों नहीं हटाया जा सकता? पांच आदमियों की कमेटी बनाई गई मेहम की हालत क्या थी देखने के लिये। उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर को युनेनिमसली हटाने का निर्णय दिया। इनको पता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नोमिनी भी वहां गये। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की नेगलीजेंस के कारण मेहम में बीसियों कत्ल हुए, लोग मारे गये। उन्होंने टाइमली नोटिस नहीं लिया। प्रेस के लिखने के बावजूद और वहा के कंडिडेट के लिखने के बावजूद वहां खून-खराबा हो गया। उन्होंने अपना एक आब्जर्वर वहां भेजा और उसने भी अपनी आंखों से डी० एस० पी० को बूथ केप्चरिंग करते हुए, मोहर लगाते हुए देखा। यह क्या छोटी बात है वहां पर 30 गांवों में चार डी.आई.जी., 16 एस०एस०पी०, 40 डी.एस.पी. डिप्लाए किए थे। हरियाणा के एक बहुत बड़े आफ़िसर ने बताया कि हम यह नहीं

समझते थे । हम यह समझते थे कि जो रिक्रूट लाये जायेंगे उनसे सादे कपड़ों में बूथ केप्चरिंग और रेंगिंग कराई जायेगी । परन्तु हमें यह पता नहीं था कि आफ़िसर ही रेंगिंग करेंगे ।

This is the confession made by very high officials in Haryana.

यह पता नहीं था कि आफ़िसर्स बूथ केप्चरिंग करेंगे । जो 40 डी.एस.पी. वहां पर लगाये गये थे उन्होंने इन 30 गांवों के अंदर बूथ केप्चरिंग की । यहां पर 16 एस.पी. और 4 डी.आई. जी., जैसा कि मैंने बताया क्यों लगाये गये थे ? जो 10-15 दिन के रिक्रूट थे, जो वहां पर पी.टी.सी., पुलिस ट्रेनिंग कालेज मधुबन में ट्रेनिंग ले रहे थे उनको वहां पर किसलिये लाया गया ? उनका वहां पर गलत इस्तेमाल किया गया । जब वहां पर आदमी मारे गये, पुलिस के दो आदमी मारे गये और वहां पर पुलिस को घेर लिया, एक डी.आई.जी. अभय सिंह को जब अंदर से निकालना चाहता था तो मोब ने उनको घेर लिया । तो अभय सिंह जो चौटाला का लड़का था उसको निकालने के लिए जब एक रिक्रूट से कहा कि अपने कपड़े इसको दे दो और वर्दी बदल लो तो उस रिक्रूट ने इन्कार कर दिया तो डी.आई. जी. ने उसकी छाती पर पिस्तौल रख दी और उसको कहा कि तुम्हें वर्दी उतारनी पड़ेगी । जब वह बाहर निकला तो दो चार हजार का जो मोब था, जो जमघटा था, उसने उसको घेर लिया क्योंकि उस बेचारे ने अभयसिंह के कपड़े पहन रखे थे । मोब ने उसको अभय सिंह समझ कर उस सिपाही को मार दिया क्योंकि अभय सिंह ने वहां के खड़कजाटान के सरपंच हरीसिंह को पोलिंग बूथ में मार दिया था । मोब को जब पता लगा कि यह अभय सिंह है तो उस सिपाही को वहां मार डाला । जब पुलिस वालों को यह पता लगा कि हमारे बहुत से आदमी गुम हैं या मारे गये हैं, यह कितने अफ़सोस की बात है, मेडम, डूब मरने की बात है, रेस्ट हाउस के ऊपर होम मिनिस्टर, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर और एक एम.पी., मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह दूसरे हाउस का मेम्बर है और एक मिनिस्टर जो दुम दबा कर भाग गया, पुलिस वालों ने वहां जा कर पीटा हरियाणा के होम मिनिस्टर, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर और एम. पी. को क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल किया गया, उनके कई साथी मारे गये । उनको पता नहीं लगा, मेडम, हुकूमत तो इनकी थी, इन को उसी वक्त भेजना चाहिये था । पांच दिन, छः दिन तक पी.टी.एस. और एच.ए.पी. के जो रिक्रूट थे, उन्होंने वापस जा कर अपनी वापसी नोट नहीं करवाई, जा ही नहीं सके । यह हुकूमत चलाना चाहते हो ? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा । (व्यवधान)

**श्रीमती सरला बहिन (उत्तर प्रदेश) : यह तो चौटाला का चौथाला है ।**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** चौटाला देवीलाल का चौथा भी और उठाला भी । यह देवीलाल को अर्थी का चौथा भी करेगा और उठायेगा भी । यह मैं आज बता देता हूं । इस महम की चौबीसी ने देवीलाल के सिर के ऊपर ताज रखा था । तीन इलेक्शन इसने जिताए । उसी महम चौबीसी के अन्दर देवीलाल आज खत्म हो चुका है । वहां बिरादरी से खारिज कर दिया गया है । वहां पर अभय सिंह को भी खारिज कर दिया है । सर्वखाप पंचायत का चेयरमैन जो कल यहां पर आया, उन्होंने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया, प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया । उसने रेजोल्यूशन पेश किया कि अभय सिंह को बिरादरी से खारिज कर दिया जाए लेकिन मेडम, मैं क्या जिक्र करूं इस बात का । तीस हजार की हाजरी ने कहा कि सारे खानदान का महम के अन्दर बहिष्कार किया जाए सिर्फ़ रणजीत सिंह को छोड़कर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? महम के अंदर जो कुछ हुआ उसके विरोध में उसके भाई रणजीत सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया । क्या ऐसे आपकी हुकूमत चलेगी ? क्या वेल्यु बस्ड पालिटिक्स यही है ? यह तो भानुमती का कुनबा है, जो कहीं की ईंट लाकर कहीं से रोड़ा लाकर जोड़ा

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

गया है । मैंने पहले भी कहा था अब फिर कह रहा हूं—

मस्जिद तो बना दी पल भर में,
इमां की हरारत वालों ने,
पर अपना मन पापी था
बरसों में नमाजी बन न सका।

[उपसभाध्यक्ष (डा० जी० विजय मोहन रेड्डी) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी जल्दी तोड़ कर कहीं से आदमी इकटठे करके क्योंकि क्लीयर मेजोरिटी तो आई नहीं, बी० जे० पी० वालों को साथ मिला लिया, सी०पी०आई०, सी०पी०आई० (एम) को साथ मिला कर हकूमत करना चाहते हैं। जब इधर बैठे थे तो बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। वेल्यू बेस्ट पालिटिक्स की बातें किया करते थे। सी० पी० आई० के नेता एन० ई० बलराम जी को सुन कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत सी नयी पालिसीज इस हकूमत ने अख्तियार की हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि बूथ केप्चरिंग, करप्शन की नयी पालिसी अख्तियार की है क्या हकूमत ने ? करप्शन का जहां तक सवाल है, हरियाणा के अन्दर क्या हुआ है। सारे हिन्दुस्तान को पता है कि पुलिस के अन्दर 3500 आदमी भर्ती किये गये और हरियाणा के अन्दर 35-35 हजार रुपये ले कर पुलिस में भर्ती किये गये। वहां पर 2 हजार से ज्यादा, 5 हजार या कितने क्लर्क लिये हैं और 20 हजार रुपये फी आदमी लिया गया है। 1700 कंडक्टर जो लिये गये हैं उनसे 10-10 हजार रूपये लिये गये हैं। इस गवर्नमेंट ने बूथ कैप्चरिंग और करप्शन की नयी पालिसीज बनायी हैं। मुझे जवाब देने के लिए तैयार हैं कि वहां क्या हो रहा है । यहां पर बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं समझ सकता कि इस गठजोड़ से ज्यादा कोई भपूंसक हो सकता है। इतनी इम्पोटेंसी कोई दिखा नहीं सकता। इनके एलाइज भी मानें, इनकी पार्टी भी मानी और इनके मेम्बर्स कमेटी ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया लेकिन उस आदमी को हटाने के बारे में कहा कि अब यह मामला पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता किस किस्म की बातें करते हो।

लेकिन आपको एक बात बताना चाहता, एलाइज भी सुन लें, जनता दल भी सुन ले कि

"आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे हैं पात,
तुम क्यों जलते पंछियो पंख तुम्हारे साथ।"

क्यों इनके साथ खत्म होना चाहते हो, ये तुम्हें खत्म करके रहेंगे, गर बचना चाहते हो तो बच जाओ वरना मैं आपको बताना चाहता हूं—अगर कोई लीडर बैठे हों तो उनको कहूं, अगर इनके प्रेजीडेंट यहां पर होते, कौन हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं अभी तक, तो उनको बताता... (व्यवधान) आप बचना चाहते हैं तो इनसे बचें। साथ ? जैसे शायर ने कहा है—

"ए जिन्दगी आ तुझे कातिल के हवाले कर दूं"

लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर तुम्हारा प्रेजीडेंट है तो यह कहे—

'ए' पार्टी आ तुझे कातिल के हवाले कर दूं

खूने तमन्ना मुझसे अब देखा नहीं जाता"

THE VICE-CHAIRMAN **(DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Please** conclude.

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक:** मैं तो कन्कल्यूड कर रहा हूं और आज बोल रहा हूं, जाता-जाता बोलने लग गया

I never thought...

मुझे कल बता दिया गया कि आपका नम्बर नहीं आयेगा और एकदम डिप्टी चेयरमैन साहिबा ने मेरा नाम ले लिया। मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं I never knew that I was going to speak. लेकिन मुझे च स दिया और आप तो समझदार हैं, हम तो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, जाते-जाते जरा थोड़ा जो कुछ हरियाणा में है आपको भी बता दें, आप भी तो इनके एलाइज हैं। नेशनल फ्रंट में वाइस चेयरमैन साहब आप भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा हूं लेकिन मैं खत्म ही कर रहा हूं। यहां पर ये इस किस्म की बातें करते थ। आज मैं बहुत कुछ देखता हूं। अपने दोस्त हैं जो इधर हैं Perhaps, I am the oldest Member in the House except one nominated Member... जो नामीनेटेड हैं वे शायद उम्र में मेरे से ज्यादा हैं। I have completed seventy-eight. तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं कन्क्लूड कर रहा हूं..(व्यवधान) वे उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम तो जाते-जाते ये चीजें सीखे हैं। अपने मेम्बरों को भी बहुत साल हो गये हैं। मैं भी ओल्ड हू यानी 20 साल से यहां पर चक्कर लगा रहा हूं, 1967 से कभी इस हाउस में कभी उस हाउस में, उस वक्त से चक्कर लगा रहा हूं फिर असेम्बलीज में भी रहा हूं पंजाब और हरियाणा की लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो इस चीज के ऊपर जाना चाहता हू कि यहां बैठे हुए जो आदमी हैं वे क्या बातें करते हैं और वहां पर जाकर क्या बातें करते हैं।

Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 am reminded of an incident which happened in a running train. In the night, when all the people, after taking their meals, were about to sleep, a gentle man got up and surprised the co-passengers 'Gentlemen, one train goes from Amritsar to Gurdaspur; the distance is 45 miles and another train goes from Amritsar to Lahore; the distance is 35 miles; could you please tell my age?' He put this question to his fellow-travellers 'Would you please tell my age?'. The other passengers began to wonder as to what the distance of the trains has got to do with the age of the questioner. However, a young man got up and said, yes, I can very well tell your age. He said, yes, you are 48. Exactly so, but how could you make it out? The young man said there is a friend of mine who is 24 but half mad. So, you appeared to be...When you sit here, you are 24 and when you go there you become 48.

(समय की घंटी)

मैं इन हालात को देखते हुए आपसे यही दरख्वास्त कर सकता हूं कि जहां वह कभी अभिभाषण की बात करते हैं और कभी फलानी चीज की बात करते हैं, वहां वह अपने घर को संभाल लें। वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स की बात को छोड़ दें, करप्शन की बात--करप्शन तो आपने एक मूल अधिकार बना दिया, मूल अधिकार में कुछ इनसर्ट करना चाहते हैं--राईट टु वर्क--राईट टु करप्शन भी उसके अंदर एड कर दो। फिर सारी चीज ठीक हो जायगी।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) कांग्रेस (आई) में यह इससे पहले हो चुका है। ... (व्यवधान)

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: आप जरा इनको संभालो। आप भी इनके साथ ही मिले हुए हैं।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं सच-सच बोलूंगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: तो आखिर में मैं ही अर्ज करना चाहता हूं कि--

छाज तो बोले, छलनी क्या बोले

[ श्री मुख्तियार सिंह मलिक ]

हमारी पार्टी की बाबत क्या जिक्र करना चाहते हैं, मुर्दे उखाड़ना चाहते हो क्या ? वह कहते हैं ना कि–

छाज तो बोले, छलनी क्या बोले,
जिसमें 7200 छेद।

तो यह बात करना आप छोड़ दें। अब मेरे बहुत से दोस्त यहां बैठे हुए हैं। दिनेश गोस्वामी जी यहां बैठे हुए हैं। वह भी शायद कुछ कहने आये हों। वह तो शरीफ़ आदमी हैं। आप अपनी पार्टी वालों को, जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है, इनको समझायें कि इस करप्शन को बंद करें, बूथ-कैप्चरिंग को हमेशा-हमेशा के लिए बंद करें।

इससे ज्यादा यानी अभिभाषण के अंदर अगर राष्ट्रपति जी इन बातों का जिक्र करते, तो मुझे बड़ी खुशी होती और मैं बोलने की भी कोशिश नहीं करता।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राम अवधेश सिंह:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब मैं उधर से इधर आया, प्रतिपक्ष से सरकारी पक्ष में गया, टैक्नीकली यहां बैठा, तो मेरी इच्छा थी कि सरकार की तारीफ़ करूं, लेकिन जिस तरह का निर्गुण अभिभाषण राष्ट्रपति जी का है, वैसा निर्गुण अभिभाषण शायद कम हुआ करता है।

यह तीन महीने के अंदर उनका दूसरा अभिभाषण है। इस सवाल को लेकर मैंने कई संयुक्त अधिवेशन में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैंने बाधा डाली और मैं चाहता था कि निर्गुण नहीं, सगुण कुछ बात कही जाए, कि टाईम-बाऊंड, समयबद्ध कोई कार्यक्रम यह सरकार करेगी कि नहीं करेगी ?

मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के बारे में पिछली दफ़ा भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं था और उसमें कोई उल्लेख नहीं था कि कब तक उसको कार्यान्वित किया जाएगा। फ़िर दुबारा तीन महीने के बाद राष्ट्रपति जी से सरकार का अभिभाषण पढ़वाया गया और फ़िर वही बात कही गई और इस ढंग से कही गई, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई सिर, पैर नहीं है और सब से बड़ी बात तो यह है, मान्यवर, कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सरकारी समिति बना दी गई, कैबिनेट उप-समिति बना दी गई और उस समिति का अध्यक्ष उस आदमी को बनाया गया, जिसने खुले तौर पर कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम भीतर से और बाहर से संघर्ष करेंगे और यह सब लोग जानते हैं कि मण्डल आयोग की सिफ़ारिशें सामाजिक आधार पर आधारित हैं। तो उस आदमी को अध्यक्ष बना दिया गया। वह उसी तरह की अध्यक्षता करेंगे जैसेकि गौरक्षा समिति का अध्यक्ष किसी कसाई को बना दिया जाय, तो वह क्या अध्यक्षता करेगा ? चौधरी देवीलाल, जोकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया और देवी लाल ने कहा कि हम इसका विरोध सरकार के अंदर और सरकार के बाहर करेंगे। इससे पता चलता है कि सरकार का इरादा क्या है ? सरकार पिछड़े वर्गों के लिए क्या करना चाहती है ? यह सबसे शर्म की बात है इस जनता दल की सरकार के लिए जिसने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आरक्षण लागू करेंगे और मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करेंगे। यह इसने वायदा किया और अपने वायदे के बारे में भूल गए। यह देश के 52 फ़ीसदी लोगों को धोखा देना है, उसके साथ न केवल विश्वासघात करना है बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जिस अल्फ़ाज में विरोध किया है कि मैं भीतर और बाहर दोनों जगह संघर्ष करूंगा, यह 52 फ़ीसदी जनता के खिलाफ़ खुल्लम-खुल्ला युद्ध का ऐलान

है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश की जनता और खासकर पिछड़ी जनता इसे अपने खिलाफ़, अपने हित के खिलाफ़ खुल्लम-खुल्ला युद्ध का उद्घोष मानेगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REEDDY): Please conclude.

**श्री राम अवधेश सिंह** : मान्यवर, अभी तीन मिनिट भी नहीं हुए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): No, no, it is four minutes.

**श्री राम अवधेश सिंह** : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बात का बहुत प्रचार हुआ है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। सके लिए एक बिल भी आने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह नोट कर ले कि "काम का अधिकार" आप लिख सकते हैं, लेकिन काम का अधिकार लिख देने से या मौलिक अधिकार की सूची में काम का अधिकार शामिल हो जाने के बाद कोई आदमी काम पाने के लिए कोर्ट में केस कर के अपना काम पा जाएगा? क्योंकि इसके मौलिक अधिकार की सूची में आ जाने से उसे काम पाने का अधिकार हो जाएगा और काम नहीं मिलेगा तो वह कोर्ट में केस करेगा कि आप वायलेट कर रहे हैं। उस वायलेशन के बाद उनको जितना भत्ता देंगे और अगर एक सौ रुपए महीना देंगे तो दस करोड़ आदमी बेरोजगार हैं तो आपको करीब-करीब 18 हजार करोड़ प्रति वर्ष देना पड़ेगा। अगर दो सौ रुपए महीना देंगे तो 36 हजार करोड़ रुपए प्रति साल देना पड़ेगा। अगर 300 रुपए महीना देंगे तो 54 हजार करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि कितना देंगे? आपका बजट क्या अलाउ करता है? क्या आप 18 हजार करोड़, 36 हजार करोड़ या 54 हजार करोड़ देंगे? क्या देंगे? एक आदमी को जीने लायक जिसमें कि वह सम्मानपूर्वक रोटी खा सके, अगर वह काम न करे तो आप उसे बेरोजगारी भत्ता कितना देंगे। यह आप देश को बताइए अन्यथा देश को दिगभ्रमित करने का झूठा नारा देने का क्या मतलब है? आप कहें कि हम अर्थ व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाएंगे ताकि लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, उसके लिए हम काम करेंगे लेकिन आप बेरोजगारी का भत्ता देने के बारे में... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Please conclude. I have given you a chance out of turn. Now please conclude.

**श्री राम अवधेश सिंह** : मुझे एक-दो मिनिट और दे दें... (**व्यवधान**)... आप कुर्सी पर हैं तो मुझे दो-तीन मिनिट तो दे दीजिए।

महोदय, इसमें इलेक्ट्रोनिक मीडिया की आजादी के बारे में भी बड़े जोर-शोर से लिखा गया है। उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है? यहां की कार्यवाही के बारे में जो चीज की जाती है, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बाधा डाली, बाधा नहीं, यह जानना चाहा कि आप टाईम-बाउण्ड प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, आपकी सरकार पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती है, इस के बारे में क्या करें? तो टेलीविजन टेलीकास्ट पर टेलीविजन वाले लोगों ने कहा कि चूंकि सेक्रेटरी–जनरल का आदेश है इसलिए जो बाधा आ रही है उसको हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। यह बोला गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेक्रेटरी-जनरल कौन होता है? सेक्रेटरी-जनरल की क्या हैसियत है कि वह कहे—संयुक्त अधिवेशन की प्रोसीडिंग के बारे में टेलीकास्ट नहीं होगा और वह फ़ालो होगा, उसको सरकारी मशीनरी फ़ालो करेगी? यह हो सकता है, मैं यह समझ सकता कि अध्यक्ष, लोक सभा

[श्री राम अवधेश सिंह]

कह सकते हैं या चेयरमैन, राज्यसभा कह सकते हैं और यह कहकर टेलीकास्ट हुआ रहता देश के सामने, देश की जनता के सामने तो हम बात समझ सकते हैं। लेकिन यह ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ। मैं चाहता हूं कि यह सदन इस बात को गंभीरता से ले कि सेक्रेटरी-जनरल ने ऐसा आदेश क्यों दिया और अगर दिया तो इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह बात सरकार के पास जाय और पूरी गंभीरता के साथ विचार हो, नहीं तो मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि सदन के लोग इस पर ब्रीच आफ़ प्रिविलेज मूव करे क्योंकि सेक्रेटरी-जनरल की हैसियत यह नहीं है कि प्रोसिडिंग के बारे में वह फ़ैसला ले। ... **(समय की घंटी)**...

मान्यवर, एक मिनिट और। अब मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (डा० जी० विजय मोहन रेड्डी)**: नहीं-नहीं। टाईम इज ओवर।

**श्री राम अवधेश सिंह**: सारे मुल्क की खनिज संपदा का 45 फ़ीसदी बिहार के गर्भ में रहते हुए भी देश का वह सर्वाधिक गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए उस तरह से तो देश मिलकर उसको लूट रहा है और जब मैं उस पर बोलना चाहता हूं तो आप रोकते हैं। थोड़ी तो मदद दें।

**उपसभाध्यक्ष (डा० जी० विजय मोहन रेड्डी)**: नहीं-नहीं। प्लीज कन-कल्यूड।

**श्रीमती सत्य बहिन**: महोदय, पहली दफ़ा इस पर बोल रहे हैं, इनको समय दे दीजिए। ... **(व्यवधान)**

**श्री राम अवधेश सिंह**: मान्यवर, तीन-चार जो केन्द्रीय सरकार की नीतियां हैं, जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही हैं 1954 से लेकर अभी तक, सरकार कभी जनता पार्टी की आ जाती है, कभी जनता दल की भी आ जाती है, कांग्रेस की ज्यादा दिन से है, उन नीतियों पर विचार जरूरी है। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाकर बिहार को लूटती रही है, जिसकी मिसाल दुनियां में नहीं है। दुनियां के अर्थ-शास्त्र का एक नियम है, विश्व के अर्थ-शास्त्र का एक नियम है कि जहां जिस चीज की खनिज संपदा होती है, उससे संबंधित कल-कारखाने वहीं खुलते हैं। लेकिन बिहार के लिए यह एक अपवाद है। बिहार में विश्व-अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत लागू नहीं है। मान्यवर, जहां एक किलो भी लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, मैंगनीज, बाक्साईट कुछ नहीं है, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां सारे कारखाने खुल जाते हैं। ... **(समय की घंटी)** ...

मान्यवर, यह जो फ्रेट-इक्वीलाइजेशन की पालिसी चालू रखी हुई है, केन्द्रीय सरकार की इस फ्रेट-इक्वीलाइजेशन की पालिसी के चलते बिहार आज कंगाल है और उसका सारा खून बाहर निकल गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब थी, उस वक्त भी मैंने यह सवाल उठाया था और मैंने कोशिश की थी इस पर हाउस की प्रोसिडिंग रोकने के लिए ताकि इस पर बहस हो। मान्यवर, फ्रेट इक्वीलाइजेशन एक अच्छे मकसद से चलाया गया था ताकि क्षेत्रीय विषमता खत्म हो, लेकिन इसके नतीजे में यह हुआ कि बिहार जो सन् 1947 में तीसरे स्थान पर था, तेईसवें स्थान पर पहुंच गया। ... **(समय की घंटी)**

मान्यवर, कनक्लूड कर रहा हूं, रायल्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम पर, जब नए प्रधानमंत्री जी गोहाटी गए, तो उन्होंने 25 परसेंट से 37 परसेंट रायल्टी बढ़ा दी, लेकिन बिहार में कोयले पर एक परसेंट से दो परसेंट भी नहीं किया। लेकिन बिहार में कोयले पर रायल्टी 1 परसेंट से 2 परसेंट भी नहीं, 1 परसेंट से 4 परसेंट

भी नहीं की गई। पेट्रोलियम पर आप देते हैं 37 परसेंट रायल्टी और कोयले पर देते हैं 1 परसेंट रायल्टी, आयरन ओर पर देते हैं सवा परसेंट रायल्टी, मैंगनीज पर देते हैं 1 परसेंट रायल्टी... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): I have given you ten minutes.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: What is this?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Next speaker. I am calling the next speaker. I have given you ten minutes.

**श्री राम अवधेश सिंह** : मैं एक शोषित राज्य की ओर से बोल रहा हूं, इसलिए आप कृपया रहम करें। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): I have given you more time, twice the time on which you had agreed. You must co-operate. After all, there are many speakers, Mr. Nallasivan, please. The next speaker. I am calling the next speaker.

**श्री राम अवधेश सिंह** : एक मिनट में कह रहा हूं। गाडगिल फार्मूले के आधार पर जब तक चलता रहेगा, जनसंख्या के आधार पर बिहार को योजना राशि में हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा और कंसाइनमेंट टैक्स को खत्म करना होगा, क्योंकि यह स्टील पैदा तो होगा बिहार में और बिकेगा महाराष्ट्र में तो कंसाइनमेंट टेक्स महाराष्ट्र सरकार को चला जाएगा, बिकेगा उत्तर प्रदेश में तो चला जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, आन्ध्र में बिकेगा तो आन्ध्र सरकार को चला जाएगा। इसको खत्म करना पड़ेगा। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Please co-operate.

**श्री राम अवधेश सिंह** : बूथ कैप्चरिंग के बारे में बोल रहा हूं ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): No, no. You have mentioned all your points. These have already come before the House. You must co-operate. No, no. You must co-operate.

**श्री राम अवधेश सिंह** : एक मिनट से दो मिनट नहीं होगा।

यहां कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया, महम में जो लूट हुई, वह घृणित है, बहुत घृणित है, उसकी निन्दा होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो लूट मचाई, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। प्रचार किया गया कि अमुक-अमुक बूथ सेंसेटिव हैं, वहां पूरा इंतजाम किया जाएगा लेकिन जहां-जहां प्रचार किया गया कांग्रेस सरकार की ओर से, कमीशन की ओर से, बिहार में वहां पोलिंग के दिन एक होम गार्ड का भी सिपाही नहीं था। इस तरह से बिहार में लूट हुई। इसलिए जिसका बल चला, उसने लूटा। कांग्रेसी लोगों ने भी लूटा और महम में भी लूट हुई। ये दोनों निन्दनीय हैं और जनतंत्र पर दोनों ओर से कुठाराघात हुआ है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए और कमीशन को इतना मजबूत किया जाए कि कमीशन सबसे ऊपर हो, पार्टी से ऊपर हो और उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वह निष्पक्ष चुनाव करा सके, स्थानीय सरकार के हाथ में खेले नहीं। धन्यवाद।

SHRI A. NALLASIVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I join my colleagues from our party and other parties supporting this Government in thanking the President for his Address.

At the outset, I want to mention that after so many months of turmoil in the country, for the ouster of the previous Government, now during the last 100 day$_3$ there has been

[Shri A. Nallasivan]

general appreciation among the general public of the manner in which the affairs of the State are being handled by the present leadership of the Government. This has been reflected in the recent Assembly election results also.

One of the main reasons for this appreciation may perhaps be that this Government is sincerely trying to arrive at a consensus on all important issues of national unity facing the country like the Punjab issue, the Kashmir issue, the Ram-Janmabhoomi issue and other major issues. The need for consensus may be due to the political compulsions of being a minority Government. Whatever may be the reason, the process of consensus offers opportunities to all well-meaning parties to offer constructive criticisms and suggestions which will help find solutions for the problems. When the solution for such complex national problems like the Punjab problem eludes the wisdom of a single party or a group of parties, what is wrong in trying to arrive at a consensus? It is normal for some political parties to make all sorts of promises at the time of elections and then forget about them or fail to implement them. But the way the present Government goes about its business indicates that it is serious in fulfilling its pledges. My colleague, Mr. Hanumantha Rao, has mentioned some of them in his speech. I want to refer to some others. The Government has taken certain steps to strengthen the democratic structure of the country. It has constituted a Committee on Electoral Reforms. The much-needed reforms on funding of elections by the Government and proportional representation to parties can be canvassed before it and legislation on those lines can be expedited. The Lok Pal Bill that has been introduced will bring even the Prime Minister under its purview. There is a Government proposal for suitable legislation to set up a high-level judicial commission for appointment of High Court and Supreme Court Judges and for the transfer of High Court Judges. If such a legislation is enacted, the scope for political considerations (and not consideration on merit) in the matter of appointment and transfer of Judges as complained of during emergency days can be reduced to the minimum. The Government's intention to amend the Official Secrets Act may help to guarantee people's right to information.

The Government has taken the initiative in involving different mass organisations of workers, peasants, agricultural workers, students, youth and women to evolve a consensus on._ the urgent demands facing these important sections of our population. The Government has promised to provide an interim relief of Rs. 360 crore for three years to victims of the Bhopal gas tragedy by providing them with the wherewithal to sustain themselves and to fight for more compensation against the American multinational company. The Address proposes a legislation to set up a national commission for women and steps to recognise womens dignity and equality. It also assures fulfilment of promises of debt relief to the small farmers and the poor by waiving loans up to Rs. 10,000. These are, of course, promises and pledges of the National Front Government, fulfilment of some of them having been already initiated. The guarantee of complete fulfilment is the mobilisation of the masses who will be the beneficiaries of these measures.

The central issue in the election was the deteriorating economic conditions of the Indian people. Increasing dependence on World Bank, a heavy foreign debt which frittered away much of our foreign exchange earnings from our export trade for payment of debt charges, a huge internal debt burden and a heavy deficit in the Central Budget which has come to Rs. 11,700 crores this year as

against the estimated Rs. 7000 and odd crores, all these factors have led to high prices of essential commodities, growing inflation, unemployment and poverty; and people, have been put to untold sufferings. This resulted in growing discontent among the mass of the Indian people. They expressed their confidence in the Janata Dal and other Opposition parties because they have pledged to bring about a change in the economic policies of the previous Government. The Address says that the objectives of the 8th Plan will be employment generation, alleviation of poverty and removal of imbalance between the urban and rural areas. The people will finally judge this Government on the basis of its performance on the economic front.

Our party has expressed its un-happiness at the way the freight rates and passengers fares have been increased in the recent Railway Budget. The increase of 10 per cent in freigh rates despite exemption for certain essential commodities, will fuel the price rise in an already difficult situation. While it is justified to increase the passenger fares for air-conditioned first class and other upper classes by 17 per cent, the sharp increase in the monthly season-tickets for second class passengers along with the allied increases like sleeper surcharges and luggage rates are going to adversely affect millions of ordinary people who depend on the railway for travel. In the earlier Presidential Address, the Government has stated that "it will revise the existing laws to bring about a suitable distribution of land and other natural resources like water and make the tiller of the land its owner". Now, the present Address confines itself only to the inclusion of the land reforms law in the Ninth Schedule. Most of these land reform laws do not go far enough and their mere inclusion in the Ninth Schedule alone will not help to solve the problem of equitable land distribution.

The important demand of the agricultural workers for a central legislation to ensure minimum wages and humane living conditiodns has not found a place in this Address. In this Address, there is also no mention of the new labour legislation which was promised to be introduced after consultation with the labour organisations in place of the amendment introduced by the previous Government in the Industrial Disputes Act. Some proposals on these have now been announced in the budget speech. We have to see how they work out.

With regard to Kashmir problem, we appreciate the efforts of the Government to arrive at a consensus of all political parties. But the Address in one place, pays compliments to the State administration for "taking all possible measures to check and curb terrorism and secessionism and to restore normalcy". Here the State Government means the Governor. If all possible measures are taken by him, what is the necessity for a new Minister-in-charge of Kashmir affairs with an Advisory Committee to help him? We know that the Kashmir problem cannot be tackled by taking administrative measures alone. All political forces that stand for national unity are to be mobilised in Kashmir. The political initiative of the Central Government in this direction is itself belittled by this formulation in the Address.

In relation to Punjab, the Address shows a sense of complacency. The initial efforts to create confidence in the minds of the Punjab people have not been quickly followed up. we feel that the Government should give top priority to the problems or Punjab.

The Assembly election results shows that the country cannot afford to be complacent about the communal situation. The growth of the influence of communal and divisive forces in some parts of the country pose a great danger to the secular fabric of our nation. The recent m-

[Shri A. Nallasivan]

cidents in Nizamuddin area of Delhi are only a pointer. So the Government should always be vigilant. The Ram-Janmabhoomi and Babri Masjid issue should be solved either through mutual discussions or through the verdict of the courts, but should not be allowed to be taken to the streets.

The Address rightly states that our policy is rooted in our commitment to non-alignment and our aspirations for a peaceful world free of domination, exploitation and war. We are glad that our Prime Minister is attending the inauguration of independence of Namibia at the head of a delegation. We are also happy that our Prime Minister is the Chairman of the Reception Committee to welcome the great national liberation leader, Dr. Nelson Mandela to our country. We also note with satisfaction that the Address assures that the pace of diplomatic exchanges between India and China is being accelerated and that subserves the interests of both our countries. Recently there was a report in the papers that in an interview to *New York Times* our Foreign Minister, Shri I. K. Gujral has stated that "non-alignment is irrelevant today". But subsequently he has issued a statement saying that he did not say so, but only that circumstances have changed and that they are to be taken into account. I am unable to understand what he means by that. We feel that the pressure of imperialists would continue to be there as a threat to the Third World and non-aligned countries and their interests demand the continuation of such a non-alignment policy. Ours biggest non-aligned country cannot afford to give it up. I want the Government to clarify its position further on this issue. . The Address, where it deals

5 P.M. with the United States of America, refers to "the objectives shared by our two democracies". In our opinion, this reference is most uncalled for. In the background of what the United States of America did to Panama and how it intervened in the elections in Nicaragua, it is not proper to compare our democracy with the U.S. democracy which does not hesitate to interfere, with subversive designs, in the internal affairs of other countries.

Finally, I would request the Government of India to insist upon the Government of Sri Lanka to fulfil its obligations to the Sri Lankan Tamils, namely (1) to devolve more autonomous powers on the North-Eastern Provincial Council and (2) to guarantee the safety and security of all sections of the Sri Lankan Tamil people. If the Government of India fails to honour its commitments in this regard, it will only help inflame the ethnic passions and the continuance of the ethnic conflict. That will ultimately help only the imperialist powers to intervene in and destabilise that region and gain a foothold in Trineomalee. I would, therefore, request the Government of India to take up this issue seriously with the Governemnt of Sri Lanka.

With these words, Sir, I conclude and I thank you for giving me this opportunity.

## STATEMENT BY MINISTER

### Accident involving No. 9020 Up Dehradun Bombay Central Express train on 14.3.1990

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, I deeply regret to apprise the House of an unfortunate accident to train No. 9020 Up Dehradun-Bombay Central Express at about 15.25 hrs. on 14.3.1990 on the Ratlam-Dahod BG Double line electrified section of the Ratlam Division of Western Railway. While this train with 16 coaches was on the run between Ratlam Junction and Morwani stations the 6 rearmost coaches derailed, of which 4 coaches, marshalled 12th to 15th from train engine, capsized at km. 646/23. As a